

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1041
दिनांक 5 फरवरी, 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी एजेंसी की उपलब्धता

1041. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) एजेंसियों की संख्या अपर्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन प्राप्त करने, समय पर रिफिल और वितरण में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र में नई एलपीजी एजेंसियों की स्वीकृति या मौजूदा एजेंसियों के विस्तार के लिए कोई सर्वेक्षण और स्थल का चयन किया है या कोई प्रस्ताव तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और उपभोक्ता मांग को ध्यान में रखते हुए नई एलपीजी एजेंसियों को शीघ्र स्वीकृति देने का है और यदि हां, तो इसकी संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने के लिए जगहों की पहचान की जाती है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एकीकृत चयन दिशानिर्देश (यूएसजी)- 2016 के अनुसार उनका विज्ञापन दिया जाता है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी गई है और एक पारदर्शी ऑनलाइन चयन प्रक्रिया लागू है। सभी आवेदनकर्ताओं को अपना आवेदन वेब-आधारित पोर्टल <https://www.lpgvitarakchayan.in> पर जमा करना होगा। ऑनलाइन चयन प्रक्रिया में आवेदन की

ऑनलाइन प्राप्ति, प्रसंस्करण और ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट आदि शामिल हैं। पात्रता, एलपीजी गोदाम के लिए ज़मीन के अवसंरचना की आवश्यकता, गोदाम के लिए उप-सड़क, शोरूम, एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए अवसंरचना आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश और चयन प्रक्रिया का विवरण www.lpgvittrakchayan.in पर दिया गया है।

01 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 25,596 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं, जिनमें से 17,668 ग्रामीण इलाकों में सेवा दे रही हैं। ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में एलपीजी की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, ओएमसी ने 01.04.2016 से 31.12.2025 के दौरान देश भर में कुल 8,027 डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरंभ की गई हैं, जिनमें से 7,434 (यानी 93%) ग्रामीण इलाकों में सेवा प्रदान कर रही हैं।

दूर-दराज और कम सुविधा वाली बस्तियों में आखरी पड़ाव तक वितरण को और बेहतर बनाने के लिए, ओएमसी ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करना, कॉमन सर्विस सेंटर - ग्राम स्तरीय उद्यमी (सीएससी वीएलई) की नियुक्ति, ऑर्डर बुकिंग और भुगतान के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल शामिल है।

रतलाम संसदीय क्षेत्र में रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिले आते हैं और यहां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के कुल 68 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं, जिनमें 58 ग्रामीण (रुर्बन, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (DKV)) डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल हैं। इसके अलावा, ओएमसी ने दो नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का विज्ञापन दिया है, जिनकी जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं	ज़िला	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रकार	तेल विपणन कंपनी
1	अलीराजपुर	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी)	आईओसीएल
2	झाबुआ	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी)	बीपीसीएल

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल

इन जिलों में अंतिम छोर तक डिलीवरी में सुधार के लिए, ओएमसी ने 61 सीएससी-वीएलई (कॉमन सर्विस सेंटर - ग्राम स्तरीय उद्यमी) इत्यादि को भी शामिल किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, इन जिलों में औसत रिफिल डिलीवरी का समय 1.5 दिनों से भी कम है।
